



जनसंपर्क टिळाज  
अमेरिकी दूतावास

# प्रेस समाचार

सांतोषध, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 फ़ोन: 011-24198000 एक्सटेंसन: 8827 फैक्स: 011-24198817  
ईमेल: [mpl@pd.state.gov](mailto:mpl@pd.state.gov) इंटरनेट वेबसाइट: <http://usembassy.state.gov/delhi.html>

25 अगस्त, 2006

## भारत-अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा विद्युत बाजार तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन पर विचार-विमर्श

नई दिल्ली -- भारत-अमेरिकी ऊर्जा विशेषज्ञों ने आज ऊर्जा बाजार की भूमिका और ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र पोर्टफोलियो प्रबंधन किस प्रकार व्यापार तथा निवेश को प्रेरित कर सकता है, पर विचार-विमर्श किया। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा बाजार में निजी क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी तथा जोखिम प्रबंधन इस क्षेत्र में निवेश जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

ऊर्जा अधिकारियों ने पेशवरों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र “इलैक्ट्रीसिटी मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट” के दौरान बातचीत की। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन साउथ एशिया रीजनल इनीशिएटिव फॉर एनर्जी ने किया था। यह अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) का एक कार्यक्रम है।

इस अवसर पर बोलते हुए यूएसएड के मिशन निदेशक जार्ज डीकुन ने कहा, “अमेरिका को आशा है कि यह कार्यक्रम पारदर्शी ऊर्जा बाजार तथा वाणिज्यिक सेवा व्यापार पद्धति को बढ़ावा देगा। इससे दीर्घावधि में ऊर्जा सुनिश्चितता प्राप्त होगी।” उन्होंने कहा कि यूएसएड ऊर्जा बाजार विकसित करने और निवेश को बढ़ाने तथा दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने की विविध योजनाओं में सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।”

श्री डीकुन ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विद्युत पेशेवरों को बाजार-आधारित विद्युत व्यापार की श्रेष्ठ पद्धति के बारे में जानकारी देने में मदद करना था। उन्होंने कहा कि यूएसएड अन्य क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ व्यापार पद्धति अपनाने तथा दीर्घकालिक सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के ऊर्जा मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है।

विद्युत सेवा संगठनों के मध्यम-स्तर के अधिकारियों के लिए एकजीक्यूटिव सत्र की शुरुआत विद्युत पोर्टफोलियो प्रबंधन पर यूएसएड के प्रशिक्षण कार्यक्रम से की गई। पोर्टफोलियो प्रबंधन जोखिम प्रबंध में सहायता करने तथा कीमतों को उचित रखने का एक उपाय है।

यह कार्यक्रम अमेरिका की ऊर्जा योजनाओं में बड़े स्तर पर अपनाया जाता है और भारत ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ऊर्जा सुनिश्चितता को प्रोत्साहन देने का प्रयास करके इसकी शुरुआत की है।

\*\*\*